†**श्री नरसिंहन्** (कृष्णगिरि) : समय बहुत थोड़ा है । मैं दो एक बातें जानना चाहता हूं । अणुशक्ति विभाग की ४०० रुपये और २५० रुपये वाली छात्रवृत्तियों के सम्बन्ध में क्या हुआ ? उस के लिये आवेदन पत्र क्यों नहीं आये ?

दूसरी बात यह है कि इन आणविक विस्फोटों के कारण वायु जो दूषित हो गई उस की जांच के साथ ही साथ हमें यह भी जांच करानी है कि हमारे आस पास के समुद्र के जल में क्या दोष पैदा हुए हैं । समुद्र के जन्तुओं तथा वनस्पतियों पर क्या प्रभाव पड़ा है । इस काम के लिये भी कुछ धन व्यय किया जाना चाहिये ।

अणुशक्ति सम्बन्धी साहित्य को अब, पहले की भांति, गोपनीय नहीं समझा जाना चाहिये ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, चर्चा के दौरान में लगभग सभी लोगों ने इस बात पर जोर दिया है कि हमें अपने देश में अणुशक्ति के विकास के लिये अधिक से अधिक कोशिश करनी चाहिये । यह विषय ही ऐसा है कि इस पर सभी लोग ख्याल करते हैं और लोगों की यह धारणा है कि हमें इस क्षेत्र में किसी भी देश से पीछे नहीं रहना चाहिये । इस सम्बन्ध में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारा इरादा किसी से भी पीछे रहने का नहीं है बशर्ते कि हमारे साधन हमें ऐसा करने दें ।

सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक दृष्टिकोण से हम यह स्वीकार करते हैं कि इस के ज्ञान तथा गवेषणा में हम किसी भी देश से पीछे नहीं रहना चाहते पर हमें इस आणविक शक्ति को शान्तिपूर्ण कार्यों में ही लगाना है । पर ध्यान रखने की बात है कि यदि हम उपलब्ध आणविक शक्ति को उसी रफ्तार से खर्च करेंगे जिस रफ्तार से आज अमरीका कर रहा है तो हमारी शक्ति एक ही दो पीढ़ियों में समाप्त हो जायेगी ।

हम जानते हैं कि हमारे देश में कोयला निकलता है तेल निकलता है और अधिक तेल निकलने की आशा भी है पर हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए यह शक्ति के साधन अधिक नहीं हैं । हमें केवल मौजूदा पीढ़ी का ही ख्याल नहीं रखना है बल्कि आने वाली पीढ़ी का भी ख्याल रखना है ।

परम्परागत साधनों के अतिरिक्त आणविक शक्ति एक महत्वपूर्ण साधन है । अतः आणविक साधनों से शक्ति तैयार करना एक महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

एक अजीब बात है कि आज से लगभग तीन या चार वर्ष पूर्व आणविक शक्ति को शक्ति के रूप में काम में लाने की बात की कल्पना बहुत अस्पष्ट थी पर अमरीका और रूस जैसे देश उस अस्पष्ट धारणा को दूर करने की कोशिश कर रहे थे । इन वर्षों में इतनी अधिक तरक्की हो गई है कि अब सभी लोग यह मानते हैं कि आणविक शक्ति का प्रयोग उपयोगी कामों में शक्ति के रूप में हो सकता है । उस समय इस बात को आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता था पर अब लोगों को पता है कि इस से आर्थिक बचत भी होगी और आगे अधिक से अधिक आर्थिक बचत की जा सकती है ।

इस समय हम में से कोई भी यह बात नहीं सोचता कि हम किसी कोयले की खान में आणविक शक्ति का संयंत्र लगायें । इस से तो शक्ति की बरबादी होगी । पर यदि आप के पास कोयला तथा जल विद्युत शक्ति न हो तो आप आणविक शक्ति को प्रयोग में लाने की बात सोच सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री जवाहर लाल नहरू]

दिल्ली का उदाहरण लीजिये । हमें ८००, ९०० या १००० मील से कोयला लाना पड़ता है । इस से परिवहन में कठिनाई होती है तथा लागत भी बहुत लगती है ।

मैं दो बातें कहना चाहता हूं । यदि भारत को प्रगति करनी है तथा जनता के रहन सहन का स्तर ऊंचा उठाना है तो उसे परम्परागत शक्ति साधनों के अतिरिक्त शक्ति के कुछ अन्य साधनों को भी प्राप्त करना होगा । दूसरी बात यह है कि हम आणविक शक्ति के समुचित विकास द्वारा इस समय ऐसा कर सकते हैं । अतः हमें इस के लिये प्रयत्न करना चाहिये और हम कर भी रहे हैं ।

अनेक माननीय सदस्यों ने आणविक शक्ति विभाग को धन्यवाद दिया । कुछ लोगों ने आलोचना भी की कि उसे इससे कहीं अधिक काम करना चाहिये था । यह बताना कठिन है कि कोई व्यक्ति कितना काम कर सकता है और कितना काम कर लेता यदि वह उस काम को एक अन्य ढंग से करता । पर यह बात सत्य है कि भारत में आणविक शक्ति विभाग का कार्य काफी तेजी से बढ़ा है । दोनों बातें ध्यान में रखी जानी चाहियें कि क्या इस से अधिक काम हो ही नहीं सकता था या हम तेज रफ्तार से चल ही नहीं सके । आणविक शक्ति विभाग अगस्त १९५४ में स्थापित किया गया था उस के पूर्व आणविक शक्ति आयोग था जो यही काम करता था ।

अगस्त १९५४ में हम ने लगभग १ · १ करोड़ रुपया आणविक शक्ति पर व्यय किया । धन से किसी बात को नापा नहीं जा सकता फिर भी इतना पता लगता है कि हम कितना काम कर रहे हैं । २ वर्ष बाद यानी चालू वर्ष में इस पर हम १२ गुनी राशि व्यय कर रहे हैं ।

यद्यपि हम धन बचाना चाहते हैं पर हम ने इस विभाग के लिये की गई धन की मांग को कभी ठुकराया नहीं । कभी कभी इस विभाग के बड़े बड़े खर्चे हमारे सामने आते हैं हम उन खर्चों को कुछ समय के लिये स्थगित कर सकते हैं पर हम ने कभी वित्तीय कारणों से इस विभाग की प्रगति को रुकने नहीं दिया है । आगे भी हम ऐसा नहीं होने देंगे ।

हमारी कुछ सीमायें हैं हम जिन के बाहर नहीं जा सकते । हम इस कार्य के वर्तमान महत्व तथा भविष्य में महत्व को मानते हैं । इसी कारण अन्य कई देशों की भांति ही भारत में भी यह विभाग प्रधान मंत्री के ही पास है ।

आणविक शक्ति के काम के दो पक्ष हैं एक गवेषणा और दूसरा गवेषणा के परिणाम का व्यावहारिक उपयोग । गवेषणा के कार्य के लिये टाटा इन्स्टीच्यूट मुख्य संस्था है । कालेजों और विश्व-विद्यालयों में भी गवेषणा कार्य किया जाता है । मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि विश्वविद्यालयों में इस कार्य को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये । मैं चाहता हूं कि विश्वविद्यालयों में जड़ मजबूत कर दी जानी चाहिये । कभी कभी यह भी देखा जाता है कि कोई व्यक्ति बिना अपनी जड़ मजबूत किये विभिन्न विज्ञानों की विशेषतया आणविक भौतिक शास्त्र को उच्च गवेषणा करने का प्रयत्न करता है । यह ठीक तरीका नहीं है विश्वविद्यालयों में आणविक भौतिक शास्त्र आदि के बारे में विद्यार्थियों की जड़ें काफी मजबूत कर दी जानी चाहियें; तभी विशेषज्ञ तैयार हो पायेंगे । इस के अलावा अब आणविक शक्ति विभाग में पहले से अधिक व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी जाती है । इस समय यह संख्या २६० के लगभग है इसे बढ़ा कर शीघ्र ही १००० तक करना है ।

ध्यान रहे कि यह ट्रेनिंग कोई साधारण ट्रेनिंग नहीं है और न साधारण व्यक्तियों के लिये है । हम ने आणविक शक्ति के सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक दोनों क्षेत्रों में इतनी प्रगति कर ली है कि संसार के अनेक बड़े बड़े आणविक शक्ति केन्द्रों में उस की प्रशंसा हुई है और उस का उल्लेख किया

जब मैं विदेश जाता हूं तो वहां के वैज्ञानिक हमारे देश में किये जाने वाले कामों के बारे में पूछते हैं। वह हमारी प्रगति की सराहना करते हैं। लगभग १ महीने पूर्व मैं नारवे के प्रो० नील्स भोर से मिला था उन्हों ने हमारे यहां के काम की बड़ी तारीफ की। वह आणविक भौतिक शास्त्र के गुरु माने जाते हैं। उन्होने हमें यह भी बताया कि वह नारवे में कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो हम पहले ही कर चुके हैं। अतः स्पष्ट है कि हम ने काफी प्रगति कर ली है। और आगे करना भी है।

हमारे देश में अनेक बुद्धिमान नवयुवक इस काम में लगे हुए हैं।

श्री तैयबजी ने पूछा कि भारतीय वैज्ञानिक लोग बाहर क्यों हैं? मैं उन को कोई उत्तर नहीं दे सकता सिवाय इस बात के कि मैं चाहता हूं कि बाहर से सीख कर हमारे नये वैज्ञानिक भारत में आकर काम करें। उन्होंने श्री गुप्त और श्री चन्द्रशेखर का नाम लिया। पिछले वर्षों में हम ने इन दोनों व्यक्तियों तथा अन्य लोगों को बुलाने की कोशिश की और वे आने को राजी भी हो गये। बाद में उन्हों ने आना अस्वीकार कर दिया। हमारी सरकार उन को आने के लिये मजबूर नहीं कर सकती। एक समय था जब भारत में इन वैज्ञानिकों के विकास के लिये पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। बाहर जा कर उन को अवसर मिला। पर आज भारत की वैसी स्थिति नहीं है। फिर भी आने वाले वर्षों में भी भारत वैज्ञानिकों को उतना वेतन नहीं दे सकता जितना अमरीका दे रहा है। अभी भारत के पास उतना वित्त नही है। मैं मानता हूं कि उन्हें आराम से रहने और काम करने के लिये काफी वेतन दिया जाना चाहिये ताकि उन के सामने आर्थिक चिन्तायें न रहें। पर, हम अन्य देशों का मुकाबिला नहीं कर सकते। हम किसी से भी यह नहीं कह सकते कि तुम भारत आओ हम तुम को वहां से अधिक वेतन देंगे। इस तरह हम मुकाबिला नहीं कर सकते।

अतः मैं चाहता हूं कि हमारे नवयुवक वैज्ञानिक अपने देश में आ कर काम करें। हमारे यहा राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में काफी गुंजाइश है।

श्री तैयबजी ने यह भी पूछा कि गवेषणा सम्बन्धी कितने पत्र निकले। मैं उन को ठीक ठीक संख्या नहीं बता सका। पर टाटा इन्स्टीच्यूट ने कई अच्छे अच्छे पत्र निकाले हैं। यद्यपि पत्र निकालने से काम की कुशलता का कोई सम्बन्ध नही है फिर भी मैं इतना कह सकता हूं कि भारत में आणविक गवेषणा के क्षेत्र मे काफी काम हुआ है।

पिछले अगस्त के महीने में हम ने तैरने के तालाब का एक रिएक्टर स्थापित किया जिस का नाम 'अप्सरा' रखा गया है। इसे भारतीय वैज्ञानिकों और भारतीय इंजीनियरों ने ही तैयार किया है। दो और नये रिएक्टर भी बनाये जाने वाले हैं।

मैं समझता हूं कि टाटा इंस्टीच्यूट में अन्य चीजों के साथ एक नई चीज के सम्बन्ध में भी गवेषणा हुई है। टाटा रिसर्च इंस्टीच्यूट संसार में प्रसिद्ध है तथा भौतिक शास्त्र के लिये दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है।

एक माननीय सदस्य ने २०० रुपये और ४०० रुपये मासिक की अधिछात्रवृत्तियों के बारे में प्रश्न किया। कोई विदेशी आवेदन पत्र नहीं आया क्योंकि यह राशि बहुत कम है। राशि को बढ़ाने का विचार किया जा रहा है। आणविक शक्ति विभाग आगामी १५ वर्षों के लिये योजना बना रहा है। हमारे यहां यूरेनियम काफी मिलता है। पर उस से ज्यादा थोरियम प्राप्त हुआ है। थोरियम

[श्री जवाहर लाल नेहरू]

बड़े महत्व का खनिज है पर उस की आवश्यकता हमें दूसरे स्तर पर पड़ेगी । पहले हमें यूरेनियम रिएक्टर बनाना पड़ेगा बाद में थोरियम का उपयोग होगा । थोरियम केवल केरल में ही नहीं बल्कि बिहार में उससे भी ज्यादा पाया जाता है ।

एक और बात मैं कहना चाहता हूं जोकि राजनीति से सम्बन्धित है कि हमें विदेशों के साधनों पर निर्भर नहीं रहना चाहिये । यदि हम विस्फोट सम्बन्धी सामग्री के लिये उन पर निर्भर रहेंगे तो हमारी विदेशी नीति पर भी उन का प्रभाव पड़ेगा । इसलिये जबकि आणविक शक्ति विकास पर एक अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण के निर्माण की बातचीत चल रही थी तभी यह बात हमारे दिमाग में आई थी । हमें यूरेनियम २३५ और प्लयूटेनियम २३३ के लिये दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ेगा यदि हम अणुबम बनाना चाहते हैं । वास्तव में हम ने पहले ही घोषणा कर दी है कि चाहे हमारे पास बम बनाने की क्षमता हो तो भी हम बम नहीं बनायेंगे । मैं समझता हूं कि भविष्य में चाहे कोई भी सरकार आवे वह इस नीति को मानेगी । ध्यान रहे यदि हम विस्फोटक पदार्थों के शोधनों के लिये दूसरे देशों पर निर्भर रहेंगे तो हमें अपनी आज़ादी में बाधायें पैदा करनी पड़ेंगी ।

विस्फोटक पदार्थों के बारे में हमें यह कहना है कि यदि इस का नियंत्रण उच्च शक्तिशाली राष्ट्रों के गुट के हाथ में दिया गया तो आणविक उपनिवेशवाद पनपेगा । हम किसी भी देश को मजबूत बनाने या कमजोर बनाने में नहीं रोक सकते और मजबूत राष्ट्र की मजबूती का असर दूसरों पर जरूर पड़ेगा । पर, हम इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते ।

त्रावनकोर खनिज कम्पनी लिमिटेड के बारे में भी कहा गया है यह कम्पनी भारत सरकार और त्रावनकोर कोचीन सरकार के एक करार द्वारा त्रावनकोर खनिज संस्थाओं को हाथ में लेने और उन में उत्पादन तथा उत्पादन के उपायों का विकास करने के लिये स्थापित की गई थी । केन्द्रीय सरकार और त्रावनकोर कोचीन सरकार दोनों के बराबर अंश थे । एक निदेशक बोर्ड था जिस में ३ प्रतिनिधि सरकार के थे और ३ राज्य सरकार के थे और उस के सभापति मि० जान मथाई नियुक्त किये गये थे । राज्य के पुनर्वर्गीकरण के बाद त्रावनकोर-कोचीन राज्य का दक्षिणी भाग त्रावनकोर कोचीन राज्य में है और दूसरा भाग मद्रास राज्य में है । वह कम्पनी अब केरल कम्पनी के नाम से बना दी गई है । मद्रास गवर्नमेंट चाहती है कि त्रावनकोर-कोचीन को मिला निदेशकत्व उसे मिल जाये जबकि केरल सरकार का दृष्टिकोण है कि यह निदेशकत्व अतिरिक्त होना चाहिये । भारत सरकार ने मद्रास सरकार की बात मान ली है क्योंकि भारत सरकार को इस से कोई अन्तर नहीं पड़ता । मामले पर समझौता हो गया है ।

मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता । यदि मैं किसी बात का जवाब देना भूल गया हूं तो उस का मुझे अफसोस है । आणविक शक्ति के चिकित्सा, कृषि तथा अन्य कामों में प्रयोग के बारे में बहुत कुछ कहा गया है । उन का प्रयोग हो रहा है और हर तरह से उन की मदद ली जा रही है । इस बात में कोई मतभेद नहीं है । इस सम्बन्ध में मेरा ख्याल है काफी तरक्की हो रही है और मैं सभा को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आणविक शक्ति विभाग अपने उत्तरदायित्व के प्रति काफी सतर्क है और सरकार भी आणविक शक्ति विभाग के महत्व को अच्छी तरह जानती है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अभी तक मेरे पास केवल एक कटौती प्रस्ताव आया है और वह श्री सम्पत का है । मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैं केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत मानूंगा जिन को माननीय सदस्य पटल पर देंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में